



# संसद प्रश्न: पृथ्वी योजना के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाएँ

प्रविष्टि तिथि: 04 DEC 2025 5:01PM by PIB Delhi

पृथ्वी योजना के लिए इसकी स्वीकृति के बाद से कुल बजट आवंटन 1385 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 685.00 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 700.00 करोड़ रुपये) है, जिसमें से आज की तारीख तक वास्तविक व्यय 1194.56 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2024-25 में 663.82 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 में 530.74 करोड़ रुपये) रहा है।

अनुसंधान परियोजनाओं को मुख्य रूप से पृथ्वी योजना की रीचआउट उप-योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। पृथ्वी के अंतर्गत वित्तपोषित अनुसंधान परियोजनाओं का राज्यवार और वर्षवार आँकड़ा अनुलग्नक I में सारणीबद्ध है।

जलवायु मॉडलिंग के लिए, मंत्रालय ने विभिन्न स्थानिक और कालिक पैमानों को लक्षित करते हुए कई उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल विकसित किए हैं, जिनमें स्वदेशी रूप से विकसित भारत एफएस (भारत पूर्वानुमान प्रणाली) वैश्विक मॉडल, जिसका उच्चतम रिज़ॉल्यूशन लगभग 6 किलोमीटर है। इसके अलावा, उच्चतम रिज़ॉल्यूशन वाली लघु-सीमा (10 दिनों तक का पूर्वानुमान) समूह पूर्वानुमान प्रणाली, और भारत में मौसमी औसत मानसून वर्षा की भविष्यवाणी के लिए मौसमी युग्मित गतिशील पूर्वानुमान मॉडल (38 किलोमीटर के उच्चतम रिज़ॉल्यूशन के साथ) शामिल हैं। जलवायु मॉडलों और प्रस्तुत व्यापक शोध से प्राप्त निष्कर्ष जलवायु रेजिलिएंस और भारत तथा विश्व स्तर पर बदलती जलवायु से जुड़े जोखिमों से निपटने के तरीकों पर भी व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं।

महासागर अनुसंधान में, इष्टतम महासागर अवलोकन नेटवर्क, परिचालन महासागर पूर्वानुमान, समुद्र तल प्रक्षेपण और महासागर पुर्नविश्लेषण के लिए एकीकृत महासागर मॉडलिंग ढाँचे का उपयोग महासागर का एक डिजिटल ट्रिन बनाने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग आपदा पूर्वानुमान के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन परिवर्तन से उत्पन्न समुद्र तल में वृद्धि, अत्यधिक समुद्र तल और ज्वारीय बाढ़ का उपयोग तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, सुनामी, उच्च तरंग अलर्ट, तूफानी लहरें, तेल रिसाव, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, प्रवाल विरंजन अलर्ट, लघु पोत परामर्श आदि से संबंधित उन्नत चेतावनी सेवाएं भारत के विशाल तटीय रेखा के किनारे रहने वाली सभी तटीय आबादी को प्रदान की जाती हैं।

भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में, भारतीय राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क के सघनीकरण से भूकंप के केंद्रों का पता लगाने और तीव्रता का अनुमान लगाने में सटीकता बढ़ी है, खासकर भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में। इसके अलावा, भूकंप के विनाशकारी प्रभावों को कम करने और भूकंप के जोखिम को कम करने के लिए 12 शहरों का भूकंपीय माइक्रोज़ोनेशन पूरा हो चुका है। इनमें से 4 शहरों (भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयंबटूर और मैंगलोर) की माइक्रोज़ोनेशन रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है।

अनुलग्नक I

राज्यों के नाम	संख्या			कुल
	2024-25	2025-26		
असम	1	2		3
अरुणाचल प्रदेश		1		1
आंध्र प्रदेश	2	1		3
दिल्ली	4	10		14
गोवा	1			1
गुजरात		2		2
हरियाणा	1	1		2
हिमाचल प्रदेश	2	2		4
झारखंड		1		1
जम्मू और कश्मीर	1	4		5
केरला	2	5		7
कर्नाटक	2	2		4
महाराष्ट्र		7		7
मध्य प्रदेश	1	2		3
नगालैंड		1		1
पंजाब	2	3		5
ओडिशा	3	10		13
राजस्थान	1	1		2
सिक्किम		2		2

तेलंगाना	2	1	3
तमिलनाडु	6	2	8
उत्तर प्रदेश	4	3	7
उत्तराखण्ड	5	9	14
पश्चिम बंगाल	7	15	22
<b>कुल</b>	<b>47</b>	<b>87</b>	<b>134</b>

### पीके/केसी/जीके

(रिलीज़ आईडी: 2199200) आगंतुक पटल : 5  
 इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu